गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 100
दि. 08.08.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

ब्राजील के राष्ट्रपति ने किया प्रधानमंत्री मोदी को फोन, ट्रंप के टैरिफ बम के बीच हुई अहम बातचीत

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से थोपे गए टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा का फोन आया। दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश जारी करने के एक दिन बाद हुआ है। भारत की ही तरह ब्राजील पर भी ट्रंप ने 50 फीसदी टैरिफ लगाया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। इस बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को याद किया।

बाद में पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति लूला के साथ

अच्छी बातचीत हुई। ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद। हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल साउथ देशों के बीच एक मजबूत, जन-केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है।

बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई। इन चचाओं के आधार पर उन्होंने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में खेती बैंक द्वारा ऋण स्वीकार कार्यक्रम आयोजित किया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सबको साथ लेकर विकास की राह पर चलने की प्रतिबद्धता से सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है - मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल*

::मुख्यमंत्री श्री::

*प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गुजरात सहकारिता आंदोलन में अग्रसर बना

*खेती बैंक राज्य के किसानों के लिए विश्वास का प्रतीक बनी है

*प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अपने शासन सेवाकाल में किसानों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और महिलाओं को सहकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए आंदोलन शुरू किया है

गांधीनगर, 7 अगस्त 2025: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 'द गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड'- खेती बैंक द्वारा आयोजित ऋण स्वीकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, विकास के पथ पर सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता से सहकारी क्षेत्र को नई दिशा मिली है।

उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना' संचालित करने का प्रस्ताव स्वीकृत

लखनऊ : 07 अगस्त, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा अन्य निर्णयों के साथ निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया :-

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) के सहयोग से 'भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिविनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना' संचालित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें यथावश्यकता किसी भी परिवर्तन/परिवर्धन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

ज्ञातव्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार तथा The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), UK के सहयोग से 'भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिविनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना' का संचालन किया जाना है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 05 प्रतिभावान छात्रों को वङ में मास्टर डिग्री लेने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इससे प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों में वङ में मास्टर डिग्री प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। प्रतिभागियों को वङ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में एक वर्ष के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक शिक्षण शुल्क के साथ परीक्षा एवं शोध शुल्क, एकल छात्र के रहने के लिये खर्च हेतु पर्याप्त मासिक भत्ता तथा निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए एक वापसी विमान किराया (इकोनॉमी क्लास) छात्रवृत्ति में सम्मिलित होगा।

ट्रंप की 50% टैरिफ की मार, क्या भारत-अमेरिका कृषि व्यापार लगेगा ब्रेक?

(जीएनएस)।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता (३१वीं ऊँ') इस समय कृषि और रूस से तेल की खरीद जैसे मुद्दों पर अटकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कृषि उत्पादों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 के पहले छह महीनों में यह व्यापार एक नया रिकॉर्ड छू सकता है।

जनवरी से जून 2025 के बीच भारत ने अमेरिका से कुल $1.69 अरब के कृषि उत्पाद आयात किए, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में हुए $1.14 अरब के मुकाबले 49.1% की बढ़ोतरी को दशार्ता है। वहीं भारत का अमेरिका को कृषि निर्यात भी 24.1% की वृद्धि के साथ $2.80 अरब से बढ़कर $3.47 अरब पहुंच गया है।

अमेरिका से भारत को होने वाले कृषि निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा "ट्री नट्स" यानी बादाम और पिस्ता का है।

2024 में इनका मूल्य $1.1 अरब से ज्यादा रहा और 2025 के पहले छह महीनों में इनमें 42.8% की सालाना बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा एथनॉल, सोयाबीन ऑयल और कॉटन (कपास) जैसे उत्पाद भी बड़े निर्यात वस्तुओं में शामिल हैं।

एथनॉल पर अमेरिका का दबाव, भारत का इनकार

एथनॉल अमेरिका से भारत को एक प्रमुख निर्यात है, जिसकी साल 2024 में वैल्यू $420 मिलियन से अधिक रही। लेकिन यह एथनॉल फिलहाल केवल औद्योगिक उपयोग - जैसे केमिकल्स, दवाइयां और अन्य उत्पादन - के लिए ही मंगवाया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत एथनॉल को ईंधन के रूप में भी आयात करे, ताकि उसे पेट्रोल/डीजल में मिलाया जा सके। लेकिन भारत ने अब तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। भारत ने अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड मकई और सोयाबीन के आयात की अनुमति नहीं दी है। अमेरिका के अधिकांश किसान मक्का और सोयाबीन ही उगाते हैं, लेकिन भारत केवल उनसे बने उत्पादों जैसे एथनॉल और तेल के आयात की इजाजत देता है, न कि अनाज या बीज के रूप में।

सम्पादकीय

राष्ट्रीय हितों से समझौता कदापि नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को प्रख्यात वृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामी नाथन की जन्मशती के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए दो टूक कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के सामानों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट जवाब देकर एक बात तो बिल्वुल स्पष्ट कर दी है कि अब भारत किसी के दबाव में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता कदापि नहीं करेगा। सवाल है कि अमेरिकी वातार्काारों की उन शर्तो को मानने से भारत के वातार्कार क्यों मना कर रहे हैं जिनके अनुसार अमेरिका के वृषि उत्पादन, मछलियां एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिले? इसका सीधा जवाब है कि अमेरिकी किसानों, मत्स्य पालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को खुद सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। यही नहीं अमेरिका में वृषि, मत्स्यपालन एवं डेयरी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रप्त है और इन तीनों ही व्यवसाय में अमेरिकी धनाढा व्यक्ति जुड़े हैं। वह भारत के किसानों, मछुआरों और डेयरी से जुड़े लोगों को बेरोजगार कर देने में पूरी तरह सक्षम हैं। इन क्षेत्रों में जो भी भारतीय जुड़े हैं उनकी आय बहुत कम है।

यदि भारत ने अमेरिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके लिए इस क्षेत्र को खोल दिया तो हमारे किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के व्यवसायियों का कारोबार तो चौपट होगा ही भारत में भी अमेरिका की तरह ही तीव्र गति से मुद्रास्फीति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी। अमेरिका शेखी बघारता है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय 54.7 लाख रुपए प्रतिवर्ष है, जो दुनिया के अन्य देशों से बहुत ज्यादा है किन्तु हकीकत यह है कि तीस ट्रिलियन डालर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है। यदि भारत ने अमेरिका के प्रति जरा भी नरमी दिखाने की गलती की तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही क्षतिग्रास्त हो जाएगी।

दुनिया में भूराजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। भारत बहुत अच्छी तरह समझता है कि हमारे देश की हालत ऐसी नहीं है कि हम अमेरिका के साथ बराबरी के स्तर पर व्यापार कर सवें। किन्तु भारत यह भी अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका का विरोध करके भी भूराजनीतिक रणनीति में वह मुश्किल में पंस सकता है। मतलब यह कि अमेरिका से न तो दोस्ती अच्छी है और न दुश्मनी अच्छी। भारत यह भी अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका से नाराज होकर चीन-रूस पर निर्भर होना भी भारतीय हितों के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए भारत के सामने समझदारी पूर्ण एक ही रास्ता है कि वह अमेरिका को इस बात का एहसास दिलाता रहे कि वह बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है।

उसके आर्थिक और सामरिक हितों के लिए घातक भारत नहीं बल्कि चीन है और ट्रंप की सारी नीतियां भारत विरोधी हैं। ट्रंप को यह भी एहसास कराने की जरूरत है कि यदि अमेरिका भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों की कब्र खोद रहा है तो तमाम सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संपन्न हुए समझौतों और संधियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भारत के लिए एक तरफ वुआं तो दूसरी तरफ खाईं है।

इसलिए बहुत समझदारी से पैसले लेने होंगे ताकि भारत के किसान, मछुआरे और डेयरी व्यवसायी का अस्तित्व भी खतरे में न पड़े और अमेरिका को भी इस बात का एहसास कराना होगा कि भारत जैसे मित्र राष्ट्र को वह अपना पिछलग्गू मानने की गलती न करे। भारत जिस तरह अमेरिका प्रशासन को खरी-खरी सुनाता वैसे ही सुनाता रहे किन्तु इस बात से पूरी तरह सजग रहे कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर आंच न आए और यह तभी संभव है जब तक कि भारत अपने नागरिकों के हितों के साथ किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं कर सकते। परिणाम वुछ भी हो। मतलब यह कि न इधर झुकें न उधर। संभल कर चलें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में जिला विकास अधिकारियों और जिला ग्राम विकास एजेंसी के निदेशकों का एक दिवसीय संयुक्त सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन 'विकसित भारत@2047' को ग्रामीण स्तर तक साकार करने में जिला विकास अधिकारियों की भूमिका बुनियादी और महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांव की भूमि को आरक्षित करने और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को और भी आसान एवं पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- ग्रामीण आवास निर्माण योजनाओं के लक्ष्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर अधिक आवासों के निर्माण से सभी के सिर पर पक्की छत का प्रधानमंत्री का संकल्प भी साकार होगा
- टेक्नोलॉजी के वर्तमान दौर में सरकारी सेवाएं जवाबदेह बनी हैं
- सत्ता का सतर्कता के साथ जनसेवा में सदुपयोग करने की स्पष्टता के साथ कार्यरत रहें
- जिला विकास अधिकारियों को ग्रामीण जनजीवन में गुणात्मक बदलाव लाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जनसेवा और अंत्योदय उत्थान की बड़ी जिम्मेदारी मिली है

ग्राम विकास मंत्री श्री राघवजी पटेल और मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी की प्रेरक उपस्थिति

गांधीनगर, (जीएनएस)। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन 'विकसित भारत@2047' को ग्राम स्तर तक साकार करने में जिला विकास अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण एवं बुनियादी बताया है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ग्रामोत्थान के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गांवों को अत्याधुनिक सुविधाओं प्रदान कर उनको तेज गति से विकास की पंक्ति में शामिल करने का संकल्प किया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसके लिए यह आवश्यक है कि जिला विकास अधिकारियों की युवा टीम ग्रामीण और गरीब जरूरतमंद लोगों तक आजीविका, आवास, आयुष्मान भारत के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय और स्वच्छता जैसी अनेक जन कल्याणाकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए सेवा भाव के साथ नेतृत्व करें।

मुख्यमंत्री ने यह बात गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित जिला विकास अधिकारियों और जिला ग्राम विकास एजेंसियों के निदेशकों के संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। सम्मेलन में ग्राम विकास मंत्री श्री राघवजी पटेल और मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में 'गाम तळ नीम' करने (गांव की भूमि को विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित करना) की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के कार्यरत होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया और भी आसान और पारदर्शी होने के कारण आवास निर्माण योजनाओं के लक्ष्य हासिल किए जा सकेंगे।

इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर और अधिक आवासों का निर्माण होने से सभी के सिर पर पक्की छत की प्रधानमंत्री की मंशा भी साकार होगी।

मुख्यमंत्री ने जिला विकास अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें ग्रामीण जनजीवन में गुणात्मक बदलाव लाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी के साथ-साथ उन योजनाओं को सफल बनाने का अवसर मिला है। इस अवसर को जनसेवा और अंत्योदय उत्थान के ईश्वरीय अवसर के रूप में स्वीकार कर पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन करने का संतोष प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने सख्ती से कहा कि गलत व्यवहार करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि हमेशा वचन, कर्म और आचरण, तीनों एक समान रखकर जनहित में काम करते हुए सरकारी सेवा को गौरवान्वित करने का भाव दिल में रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के आज के दौर में सरकारी सेवाएं जवाबदेह बन गई हैं। इतना ही नहीं, लोगों की जागरूकता भी बढ़ गई है, तब योजनाओं की क्रियान्वयन टीम के प्रमुख के रूप में जिला विकास अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य, समयबद्ध आयोजन और लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

इण्डिया ब्लॉक के नेताओं के साथ डिनर पार्टी में राहुल गांधी ने दिखाए चुनाव में धोखाधड़ी के सबूत, एसआईआर पर चर्चा हुई

(जीएनएस)। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार शाम नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर रात्रिभोज के लिए बैठक की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'चुनावी धांधली' के कथित आरोपों पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ गहन चर्चा की। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को सबूतों के साथ एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दी।

इस बैठक में 25 से अधिक दलों के लगभग 50 नेता शामिल हुए। इस बैठक में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (रक्फ़) और राहुल गांधी द्वारा लगाए गए बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों पर मुख्य रूप से बात हुई।

यह बैठक भले ही अनौपचारिक थी, लेकिन इसने विपक्षी नेताओं के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में काम किया। उन्होंने उन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाओं और रुख को मजबूत करने का प्रयास किया, जिन्हें कई लोगों ने लोकतांत्रिक अखंडता के लिए खतरा बताया। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और महबूबा मुफ्ती को भी आपस में बात करते देखा गया।

चुनावों में "बड़ी आपराधिक धोखाधड़ी" के सबूत पेश किए

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के आम चुनावों में "बड़ी आपराधिक धोखाधड़ी" के सबूत पेश किए। नेताओं को दिए गए एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में, गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोट "चुराए" गए थे, जिसके लिए उन्होंने पांच अलग-अलग तरीकों से हेरफेर का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने धांधली को आसान बनाने और वास्तविक मतदाता भागीदारी को दबाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के साथ "मिलीभगत" की है। याद रहे राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में कथित वोट चोरी का जिक्र करते हुए कहा था, "यह सिर्फ एक अनियमितता नहीं है; यह हमारे लोकतंत्र पर एक परमाणु बम है।" इस रात्रिभोज में कमल हासन और गौरव गोगोई भी राहुल गांधी के घर पर मौजूद थे।

11 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकालेगा इंडिया गठबंधन

गौरव गोगोई के अनुसार, राहुल गांधी की प्रस्तुति में 'चुनावी धांधली' से संबंधित पुख्ता सबूत पेश किए गए। प्रस्तुति के बाद, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने 11 अगस्त को चुनाव आयोग (एउक) तक मार्च निकालने का फैसला किया है। यह कदम चुनाव में कथित धांधली के आरोपों के खिलाफ एक संयुक्त और सशक्त विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

जो बिहार में हो रहा है, वह देश में कहीं भी हो सकता है

बिहार में चल रहा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (रक्फ़) एक विवाद का केंद्र बन गया है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि इस प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर मताधिकार का हनन हो सकता है, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों और अल्पसंख्यकों का। बैठक का माहौल सकारात्मक रहा और सभी नेताओं ने इस गंभीर विषय पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने इस बैठक को "बहुत सार्थक" बताया और मतदाता पहचान, सूची में हेरफेर और चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शिता की कमी पर चिंता व्यक्त की। राजा ने चेतावनी देते हुए कहा, "जो बिहार में हो रहा है, वह देश में कहीं भी हो सकता है।

अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित किताबों का मुद्दा भी उठाया

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांगों को दोहराया और सरकार पर इस वादे को पूरा करने में देरी करने के लिए आलोचना की। अब्दुल्ला ने कहा, "हमने जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित किताबों का मुद्दा भी उठाया। यह असंवैधानिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए।" कोई औपचारिक एजेंडा नहीं था, लेकिन मुख्य विषय स्पष्ट था: विपक्षी दलों के बीच एकता, जिसे वे बढ़ते संस्थागत समझौते के रूप में देखते हैं। राहुल गांधी को फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके आवास पर रात्रिभोज के दौरान देखा गया।

इस शाम को राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति देखी गई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल थे। प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं में शरद पवार (एनसीपी-एसपी), उद्धव ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी), अखिलेश यादव और डिंपल यादव (एसपी), तेजस्वी यादव (राजद), अभिषेक बनर्जी (टीएमसी), महबूबा मुफ्ती (पीडीपी), कमल हासन (एमएनएम), और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और सीपीआई (एम) के एम.ए. बेबी, सहित अन्य शामिल थे। फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस के गुटों, एमडीएमके, आरएसपी, वीसीके, पीडब्ल्यूके, आरएलपी और केएमडीके के नेता भी उपस्थित थे।

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर फिर हमला! गोल्डी-लॉरेंस गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी, दी ये चेतावनी

(जीएनएस)। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के सरे स्थित 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, जिसने सनसनी मचा दी है। 7 अगस्त 2025 को हुई इस ताजा फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लोंऔर लॉरेंस बिश्नोई गैंगने ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग ने धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो अगला हमला मुंबई में होगा।

यह दूसरी बार है जब कपिल के कैफे को निशाना बनाया गया, इससे पहले 9 जुलाई 2025 को भी कैफे पर गोलियां चलाई गई थीं। मुंबई पुलिस और कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की जांच में जुट गई हैं। आखिर क्यों बार-बार निशाने पर है कपिल का कैफे? क्या है इस सनसनीखेज क्राइम की कहानी? आइए, इस खौफनाक वारदात को डिकोड करते हैं...

कैप्स कैफे पर फिर फायरिंग: 9 सेकंड का खौफ

7 अगस्त 2025 को देर रात कनाडा के सरे (२४११८) में कैप्स कैफे पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक 9 सेकंड के वायरल वीडियो में दर्जनभर से ज्यादा गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। हमलावरों ने कैफे की खिड़कियों को निशाना बनाया, जिससे संपत्ति को भारी नुकसान हुआ, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। यह कैफे, जिसका संचालन कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ करती हैं, 4 जुलाई 2025 को सॉफ्ट लॉन्च के बाद से ही विवादों में है।

सरे पुलिस सेवा ने बताया कि उन्हें रात 1:50 बजे (स्थानीय समय) 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में गोलीबारी की सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक, 'घटनास्थल पर गोलियां चलने की पुष्टि हुई। कर्मचारी अंदर मौजूद थे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ।' फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट टीम जांच में जुटी है, और संभावित मकसद व अन्य घटनाओं से संबंध की पड़ताल कर रही है।

गोल्डी ढिल्लों-लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी

फायरिंग के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी मचा दी, जिसमें गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा, 'जय श्री राम, सत श्री अकाल। राम राम सभी भाइयों को। आज सरे में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। हमने टारगेट को कॉल किया था, लेकिन रिंग नहीं सुनी। अब भी नहीं माना, तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी।'

पटना, सऊदी कंपनी के इंटरव्यू रूम में खुला फर्जीवाड़े का राज, असली पासपोर्ट और नकली चेहरा

(जीएनएस)। क्या हो अगर कोई आपका असली पासपोर्ट लेकर विदेश इंटरव्यू देने चला जाए, बस तस्वीर बदल कर? और क्या हो जब एक इंटरव्यू रूम में यह राज खुल जाए कि एक ही पासपोर्ट नंबर पर दो-दो चेहरे मौजूद हैं?

सऊदी अरब की एक प्रतिष्ठित कंपनी के इंटरव्यू में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पटना से इंटरव्यू देने पहुंचे कुछ अभ्यर्थियों के पास असली पासपोर्ट तो थे, लेकिन चेहरे उनके नहीं थे! यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक हाई-टेक पासपोर्ट क्लोनिंग रैकेट का हिस्सा है, जिसने अंतरराष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया को भी चौंका दिया।

इंटरव्यू रूम में खुली पोल

सऊदी कंपनी द्वारा आयोजित इंटरव्यू में जब दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, तो अधिकारियों ने पाया कि पासपोर्ट नंबर और नाम सही है लेकिन तस्वीर बदली हुई है। वीडियो में आप देख सकत हैं कि किस तरह से फजीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था।

नकली नहीं, असली पासपोर्ट पर तस्वीर बदलवाने का हाई-टेक खेल!

सूत्रों के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों के पास यह पासपोर्ट थे, वह किसी और के असली दस्तावेज थे, जिनमें तस्वीर बदलकर नया चेहरा चस्पा किया गया था। नाम, पता, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ असली। बस तस्वीर जालसाजों द्वारा बदल दी गई थी।

पटना में चल रहा था "पासपोर्ट क्लोनिंग" का रैकेट

जांच में यह भी सामने आया है कि पटना में एक सुनियोजित गिरोह काम कर रहा है, जो बेरोजगार युवाओं को सऊदी जैसे देशों में नौकरी का झांसा देकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने की सुविधा देता है। इस गिरोह का नेटवर्क इतने हाई-टेक तरीके से काम करता है कि पासपोर्ट असली होता है, लेकिन चेहरे और नीयत फर्जी!

वीडियो वायरल, एजेंट फरार, मोबाइल नंबर बंद

इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आते ही स्थानीय एजेंट का मोबाइल नंबर बंद हो गया है और ऑफिस पर ताला लटका हुआ है। कई अभ्यर्थी अब डर के मारे चुप हैं, जबकि जिनके नाम पर पासपोर्ट क्लोन किए गए, वे खुद अनजान हैं। इतना ही नहीं शातिरों के पास कई फजी पासपोर्ट के सहारे विदेशों में खुलेआम आना जाना भी कर रहे हैं।

इमिग्रेशन विभाग सक्रिय, सऊदी कंपनी ने भेजी शिकायत

अब भारत का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। सऊदी कंपनी ने भी इस फजीवाड़े की औपचारिक शिकायत भारत सरकार को भेज दी है, और आशंका है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। वहीं कुछ शातिर के विदेश भाग जाने की खबर भी सामने आ रही है।

कानून क्या कहता है?

भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अनुसार, "दूसरे के नाम पर यात्रा करना या उसके दस्तावेज का उपयोग करना एक आपराधिक कृत्य है।

जिसकी सजा कई वर्षों की जेल और विदेश यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध हो सकता है।" इस फजीवाड़े ने न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि बेरोजगार युवाओं के शोषण और सरकारी तंत्र की कमजोरियों को भी उजागर किया है। अब देखना यह है कि इस 'चेहरे की चोरी' के पीछे असली चेहरे कितने बड़े हैं।

कौन हैं आईएएस अभिषेक प्रकाश, करीबी के घर ईडी ने दी दबिश? कुछ महीने पहले हो गए थे सस्पेंड

(जीएनएस)। भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक समय तेज-तर्रार और भरोसेमंद अफसर माने जाने वाले IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश आज कई जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। IIT से पढ़ाई करने वाले और यूपी के कई जिलों में जिलाधिकारी रह चुके अभिषेक प्रकाश पर अब सोलर प्रोजेक्ट में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी कंपनी से प्रोजेक्ट पास कराने के लिए 5% कमीशन की मांग की थी, और यह काम उन्होंने अपने करीबी निकांत जैन के जरिए करवाया।

मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंचने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई, जिसके बाद कऊर अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। अब जब ED ने उनके सहयोगी निकांत जैन के ठिकानों पर छापा मारा है, तो साफ हो गया है कि यह मामला सिर्फ एक रिश्वतखोरी का नहीं, बल्कि एक गहरे नेटवर्क की परतें खोल सकता है। उनके करीबी निकांत जैन के ठिकानों पर एऊ यहां यह कार्रवाई सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ी घूसखोरी की शिकायतों के बाद की है। अधिकारी की छवि, सत्ता से नजदीकी और अब बढ़ती जांच-ये सभी बातें इस पूरे मामले को और भी पेचीदा और अहम बना देती हैं।

अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के कऊर अधिकारी हैं। वे यूपी में कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, जिनमें लखनऊ और अलीगढ़ जैसे जिलों के जिलाधिकारी से लेकर 'Invest UP' के CEO तक की जिम्मेदारी शामिल रही है। वे IIT से पढ़े हुए अधिकारी हैं और उन्हें एक समय सरकार का भरोसेमंद अफसर माना जाता था।

यह पूरा मामला SAEL सोलर कंपनी से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी थी कि अभिषेक प्रकाश की ओर से 5% कमीशन मांगा गया। इस काम के लिए उनके कथित करीबी निकांत जैन को मध्यस्थ बनाया गया था। बाद में निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस घोटाले में मुख्य आरोपी बताया गया।

अभिषेक प्रकाश पर अब तक कुल पांच जांचें चल रही हैं। इनमें दो विभागीय जांच, एक पुलिस जांच, एक सतर्कता जांच (विजिलेंस) और एक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच शामिल है। यूपी सरकार ने उन पर 'All IndiÔ Services Conduct Rules' के तहत चार्जशीट भी जारी कर दी है।

ED की छापेमारी में बढ़ी हलचल

अब जब एऊ ने निकांत जैन के ठिकानों पर छापा मारा है, तो माना जा रहा है कि जांच अब और तेज हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, एऊ को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं, जो पूरे नेटवर्क को उजागर कर सकते हैं।

उ0प्र0 में आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा एवं नवीकरण अवधि के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-305(1) में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत

लखनऊ (जीएनएस)। : 07 अगस्त, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा अन्य निर्णयों के साथ निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया :-

मंत्रिपरिषद ने आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा एवं नवीकरण अवधि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-305(1) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

अधिनियम में उक्त संशोधन के आधार पर नगर निगम स्तर पर उत्तर प्रदेश नगर निगम (चिन्हों एवं विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली-2025 का क्रियान्वयन किया जाना है। वर्तमान में नगरीय जनसंख्या एवं क्षेत्रफल/सीमा विस्तार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बदलते नगरीय परिदृश्य में प्रदेश के नगर निकायों के दायित्वों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नगर निगमों के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण दायित्वों के पूर्ण निर्वहन हेतु निकाय में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा या नवीकरण की अवधि दो वर्ष के स्थान पर पन्द्रह वर्ष करने से विज्ञापन हेतु विज्ञापन एजेंसियों के लिये वृहद निवेश, नवाचार, अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। लम्बी अवधि की अनुज्ञा से बार-बार निविदा प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त होती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है एवं नगर निगमों को दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता प्राप्त होती है। वर्तमान में विज्ञापन के क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में तकनीकी नवाचारों के अनुप्रयोग एवं गुणवत्ता सुनिश्चत करने के लिए दीर्घ अवधि के निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अधिनियम में संशोधन से नगर निगमों में विज्ञापन हेतु विज्ञापन एजेंसियों के लिये निविदा को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, सुविधाजनक एवं व्यापक बनाया जा सकेगा। मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश-2025 प्रख्यापित किया जाएगा।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

बदलते परिवेश की आवश्यकता के दृष्टिगत उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम औद्योगिक आस्थान प्रबन्धन नीति का आलेख अनुमोदित

लखनऊ : (जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा अन्य निर्णयों के साथ निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया :-

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम औद्योगिक आस्थान प्रबन्धन नीति का आलेख अनुमोदित किया है। इस नीति के किसी भी बिन्दु में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्धन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

ज्ञातव्य है कि औद्योगिक आस्थानों की स्थापना 1960 के दशक में किए जाने के उपरान्त इनके प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 1978 से लेकर वर्ष 2022 तक औद्योगिक आस्थानों के भूखण्ड/शेडों के आवंटन, हस्तान्तरण, पुनर्जीर्वीकरण आदि के सम्बन्ध में अलग-अलग शासनादेशों के माध्यम से व्यवस्था की गयी, जो समय की मांग तथा प्रबन्धन में दिन-प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे।

बदलते परिवेश की आवश्यकता के दृष्टिगत विभाग के औद्योगिक आस्थानों की सम्पतियों के उचित रख-रखाव, अधिकारों का स्पष्ट विभाजन तथा कुशल प्रबन्धन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये एक समेकित शासनादेश निर्गत किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :-

औद्योगिक आस्थानों में उपलब्ध/रिक्त औद्योगिक भूमि/शेड/भूखण्ड आवंटन लीज/रेण्ट पर नीलामी/ई-ऑक्शन के आधार पर किया जाएगा। लीज/रेण्ट की अवधि का निर्धारण एवं नीलामी हेतु माध्यम/पोर्टल का निर्णय आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा लिया जाएगा।

प्रदेश की भौगौलिक संरचना तथा व्यापक फैलाव के दृष्टिगत मध्यांचल हेतु भूखण्डों के आवंटन की रिजर्व प्राइस 2,500 रुपये प्रति वर्गमीटर, पश्चिमांचल हेतु इससे 20 प्रतिशत अधिक अर्थात 3,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल हेतु इससे 20 प्रतिशत कम अर्थात 2,000 रुपये प्रति वर्गमीटर वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित होगी। प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को यह दर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ निर्धारित होगी। ई-ऑक्शन में प्रतिभागिता हेतु आवेदक को भूखण्ड के प्रदर्शित आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करनी होगी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 35 (बी) के अन्तर्गत हायर परचेज एग्रीमेण्ट को अनिश्चितकालीन पट्टा माना जाएगा और इस पर स्टाम्प, विक्रय पत्र की भांति देय होगा। शेड सहित अन्य सभी निर्माण की लीज/पट्टा अनिश्चितकालीन होगा और उसका विक्रय आवंटी का माना जाएगा।

राज्य में नया इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण प्रिय और आधुनिक बन रहा है: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में क्रेडाई गुजरात की 'चेंज ऑफ गार्ड' सेरेमनी आयोजित हुई

मुख्यमंत्री:-

- इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा रियल एस्टेट क्षेत्र में किसी भी स्थिति को संभाल लेंगे, इस आत्मविश्वास के साथ यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है
- रियल एस्टेट क्षेत्र की नीति निर्माण प्रक्रिया में रचनात्मक सुझाव प्रदान करके सहभागी बने
- निर्माण क्षेत्र को ग्लोबल स्टेंडर्ड के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाना है

गांधीनगर, 07 अगस्त :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में क्रेडाई गुजरात द्वारा वार्षिक सामान्य सभा और 'चेंज ऑफ गार्ड' सेरेमनी का आयोजन अहमदाबाद में किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में क्रेडाई गुजरात के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई।ये नए पदाधिकारी आगामी 2025-26 कार्यकाल के लिए

पदभार ग्रहण करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आज दुनिया जानती है कि भारत वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बना है। इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा रियल एस्टेट क्षेत्र में किसी भी स्थिति को संभाल लेंगे, इस आत्मविश्वास के साथ यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है।

उन्होंनें गुजरात सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीतियों की भूमिका बताते हुए कहा कि इन नीतियों के कारण राज्य में नया इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण प्रिय और आधुनिक बन रहा है।उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र सरकार की नीतियों से संतुष्ट है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नयी कंस्ट्रक्शन साइट में ग्रीन कवर और वॉटर हार्वेस्टिंग जैसे पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि गुजरात का रियल एस्टेट क्षेत्र रचनात्मक सुझाव देकर नीति निर्माण प्रक्रिया में सहभागी बने। उन्होंनें 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने।

सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र के सभी आवेदनों को सुनने के लिए तैयार है और साथ ही कोई इसका गलत लाभ न ले जाए, इसका भी सरकार ध्यान रखती है।

उन्होंने कहा कि हमें निर्माण क्षेत्र को ग्लोबल स्टेंडर्ड के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। हर योजना ग्लोबल स्टेंडर्ड की बने और एक इंच का भी गलत निर्माण न हो, हमें ऐसे दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है।

इस अवसर पर श्री ध्रुव पटेल ने कहा, "अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी, ओलंपिक ड्रीम और धोलेरा जैसी बड़ी परियोजनाएं मिली हैं, इसलिए अहमदाबाद आधुनिक युग के एक नए मोड़ पर खड़ा है। गुजरात और विशेषकर अहमदाबाद में रियल एस्टेट क्षेत्र का विकास राज्य सरकार के सहयोग के साथ तेजी से ऊंचाइयों को छू रहा है।

इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष श्री आलाप पटेल ने कहा कि अहमदाबाद समग्र देश की फाइनेंशियल कैपिटल और इंडस्ट्रियल हब बनने की ओर अग्रसर है।समग्र विश्व का ध्यान अहमदाबाद के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर है, तो रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।"

इस कार्यक्रम में क्रेडाई गुजरात और अहमदाबाद के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ गुजरात के रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए सरकार और उद्योग के बीच सहकार को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद सहित समग्र गुजरात के रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े व्यवसायी उपस्थित रहे।

कुपोषित बच्चों के लिए 8 रुपए, गाय पर 40 रुपए खर्च कर रही मोहन यादव की सरकार, देखिए रिपोर्ट

(जीएनएस)।

आज से 20 साल पहले पारले जी बिस्किट का पैकेट सिर्फ चार रुपए का था जो कि अब पारले जी का 10 रुपए का मिलता है। लेकिन, सवाल ये है कि क्या 8 रुपए में किसी भूखे बच्चे की भूख मिट सकती है? क्या कोई बच्चा जो भूख से मरने की कगार पर हो उसके लिए 12 रुपए में इतना आहार आ सकता है कि वह अति कुपोषित की श्रेणी से बाहर आ सके? जवाब एक दम साफ है नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार का ताजा डेटा सामने आया है।

दरअसल राज्य के बच्चों में, खासकर कि शिशुओं में कुपोषण की स्थिति गंभीर है, आज से नहीं सालों से यही स्थिति है। इसे लेकर जब सवाल पूछे गए तो मोहन यादव की सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विधानसभा में आंकड़े पेश किए। जिसके मुताबिक राज्य में हर एक कुपोषित बच्चे के पोषण पर सरकार रोजाना 8 रुपए और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर 12 रुपए खर्च कर रही है।

अधिकारी खा रहे ड्राई फ्रूट्स

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए गए जवाब के बाद, कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने फिर से सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब दूध ₹70 प्रति लीटर बिक रहा है, तो बच्चों को इस नाममात्र की राशि में उचित पोषण कैसे मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों की बैठकों में होने वाले हजारों रुपये के नाश्ते और सूखे मेवों के खर्च की तुलना कुपोषित बच्चों के लिए दी जा रही राशि से की।

मध्य प्रदेश में कुपोषण की गंभीर स्थिति

राज्य में कुपोषण एक गंभीर और हर पल बढ़ने वाली एक बड़ी समस्या है। खासकर आदिवासी इलाकों में। श्योपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे आदिवासी बहुल जिलों में हालात ज्यादा खराब है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जिलों में हर चार में से एक बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। यानी कि करीब 25 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की जद में हैं।

डेढ़ लाख बच्चें कुपोषण के शिकार

सरकारी डेटा को ही सही मान लें तब भी राज्य में कुल 1.36 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनमें से 29,830 की हालत इतनी खराब है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जबकि 1 लाख 6 हजार बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की कुपोषण दर 7.79 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 5.40 प्रतिशत से काफी अधिक है।

आंगनवाड़ी केंद्र के हाल

राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। कैसे काम कर रहे हैं कुछ नहीं पता। लेकिन आंकड़ा कहता है कि यही आंगनवाड़ी केंद्र कुपोषित बच्चों को ₹8 प्रतिदिन और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को ₹12 प्रतिदिन पूरक पोषण आहार देते हैं। कभी किसी आंगनवाड़ी केंद्र में दो तरह का खाना देखा है आपने? आंगनवाड़ी केंद्रों में या तो दलिया आता है या पोहा आता है जो सबको दे दिया जाता है। जिसकी क्वालिटी भी कई बार दुनिया के सामने आ चुकी है।

क्या बोलीं जिम्मेदार मंत्री निर्मला भूरिया?

सदन में बता हुई तो महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने भी स्वीकार किया है कि यह राशि कम है और उन्होंने केंद्र सरकार से अधिक फंड की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि कई अन्य राज्यों ने भी पोषण आहार भत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है।

किशोर दा के 96वें जन्मदिन पर अहमदाबाद में एक भव्य तीन-दिवसीय मेगा सेलिब्रेशन सम्पन्न

महान गायक और हरफनमौला जीनियस, किशोर कुमार जी, जिन्हें हम प्यार से किशोर दा भी कहते हैं, के 96वें जन्मदिन पर अहमदाबाद में एक भव्य तीन-दिवसीय मेगा सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। "हर रंग किशोर दा के संग" नामक यह आयोजन मेलोडी मेकर्स म्यूजिकल ग्रुप और क्रॉक स्टूडियो के सहयोग से हुआ।

खचाखच भरे मिनिटोरियम में, इस सेलिब्रेशन में उनके 96वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 96 गीतों की एक आधिकारिक श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिसके बाद श्रोताओं की फरमाइशें भी पूरी की गईं। शिवशंकर बुंदेला और मीनू सिंघवी मोतियानी जी ने क्रॉक की पूरी टीम के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गीतों को पेश किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ मनहर शुक्ल जी ने किया, जिन्होंने किशोर कुमार साहब के जीवन के कई रोचक पहलुओं को छूकर इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया।

स्योहारा ठाकुरद्वारा रोड गांव बरखेड़ा के पास हाइवे रोड पर हो रहा है जल भराव

स्योहारा , बारिश के पानी से हुई गांव को जोड़ने वाली रोड बंद भर गया रोड पर पानी। स्योहारा ठाकुरद्वारा रोड गांव बरखेड़ा के पास हाइवे रोड पर हो रहा है जल भराव लोगो का हुआ जीना दुश्वार। स्योहारा से गांव को जाने वाले लोग ले रहे है टेक्टर ट्रालियों का सहारा। टेक्टर ट्राली वाले स्वामी कुछ खर्चा तेल का लेकर करा रहे है रोड पार। इस आबदा की घड़ी में ए डी एम बिजनोर ने कुछ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुचकर लिया जायजा। लोगो से कहा किसी भी परेशानी में हम आप के साथ

खड़े है। वही मिली जानकारी के अनुसार बेरखडा गांव के किसी परिवार के दो बेल की इस पानी के कारण मृत्यू हो गई वही अधिकारियों ने मृतक बेल के स्वामियों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। वही थाना प्रभारी स्योहारा की टीम भी इस आबदा की खड़ी में लोगो के लिए सतर्क है।

श्री अग्रसेन कन्या पी.जी. कॉलेज में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

(जीएनएस)।

श्री अग्रसेन कन्या पी.जी. कॉलेज वाराणसी के बुलानाला परमानंदपुर परिसर में दिनांक 7. 8.2025 को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत विविध कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा रंगोली प्रतियोगिता तथा संगीत विभाग एवं सांस्कृतिक केंद्र की छात्राओं द्वारा देश भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इसी क्रम में महाविद्यालय की छात्राओं एवं एन.सी.सी. कैडेट्स द्वारा संविधान रैली निकल गई। कार्यक्रम में प्रो कुमुद सिंह प्रो आभा सक्सेना डॉ अपर्णा शुक्ला डॉ वेणु वनिता डॉ सुनीता सिंह डॉ चंदा रानी डॉ प्रियंका झा डॉ नीता दिसावाल डॉ शिवानी शुक्ला इत्यादि अनेक प्रवक्तागण सम्मिलित हुए।

गृह विज्ञान विभाग द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह 1-7 अगस्त के अवसर पर हरहुआ पंचायत भवन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां स्तनपान करने वाली महिलाओं को विभिन्न खाद्य सामग्री जैसे सठौरा लड्डू अछवानी बनाना सिखाया गया। तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के विषय में भी बताया गया। इस अवसर पर गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो अनीता सिंह डॉ अंजली त्यागी डॉ विभा सिंह डॉ नीलू गर्ग श्रीमती माधुरी यादव तथा छात्राएं उपस्थित रही।

आला अधिकारियों से लगाई महिला ने इंन्साफ की गुहार

(जीएनएस)।

स्योहारा।अला अधिकारियों ने दिए क्षेत्राधिकार धामपुर को जांच कर कार्यवाही के आदेश स्योहारा थाना प्रभारी पर अभद्रता, मानहानि और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। महिला पत्रकार एवं राष्ट्रीय हिंदी दैनिक आज का दहकता सूरज की मीडिया विज्ञापन इंचार्ज किश्वर जहाँ ने जिला अधिकारी बिजनौर को दिए प्रार्थना पत्र में थाना प्रभारी स्योहारा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि किश्वर जहाँ एक सम्मानित पत्रकार और समाजसेवी के रूप में क्षेत्र में अपनी पहचान रखती हैं। जिसके बाद भी थाना प्रभारी ने उनके विरुद्ध बिना किसी साक्ष्य और बिना उचित प्रक्रिया के फर्जी शिकायती पत्रों का सहारा लेकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे है। पीड़ित ने एक युवक के विरुद्ध पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि ऑनलाइन माध्यम से जान से मारने की धमकी दी जा रही है और परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। किश्वर जहाँ का कहना है कि प्रभारी स्योहारा मामले का संज्ञान लेकर भी कोई कार्यवाही नही कर रहे है। यह हरकत न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा का हनन है, बल्कि पत्रकारिता और लोकतांत्रिक पर सीधा प्रहार है।

गौरतलब है कि थाना प्रभारी स्योहारा पर इससे पहले भी वकीलों, ग्राम प्रधानों और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लग चुके हैं,वही थाना प्रभारी की पत्रकारो को गाली देने वाली ऑडियो भी वायरल हो गई है। लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पत्रकार समाज और स्थानीय लोग इस मामले में उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और थाना प्रभारी स्योहारा के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का शिक्षा-उन्मुख अहम और दूरगामी निर्णय

गांधीनगर, 07 अगस्त : गुजरात सरकार मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2.0 के अंतर्गत चयनित राज्य के ग्रांट इन एड माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को ढांचागत सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

यह सहायता गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड से संबद्ध और शिक्षा विभाग के अंतर्गत ऐसे ग्रांट इन एड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों को 80:20 के अनुपात में दी जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद यह सुनिश्चित करने की सिफारिशें की गई हैं कि छात्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करें।

राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन विशेषकर, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य में ग्रांट इन एड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन करते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग की ओर से उठाए जा रहे परिणामोन्मुखी कदमों के फलस्वरूप ऐसे स्कूलों में आने वाले छात्रों की संख्या में बड़ी वृद्धि होने की भी संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों के संबंध में दूरदर्शी योजना के साथ ग्रांट इन एड स्कूलों में भी सरकारी स्कूलों की तरह ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है।

बहराइच युवक से बीजा देकर सउदी भेजने के नाम पर डेढ़ लाख डकारे पीड़ित कैसरगंज थाने से लेकर कई जगह भेज शिकायती पत्र

(जीएनएस)।

बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुडौनी गांव निवासी मोहम्मद सुफियान पुत्र बाबू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश व एसपी रामनरायन सिंह को पत्र भेजकर उनके साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही व उनसे लिए गए 143500 के वापसी की मांग की है। आरोप है कि फिरोज अहमद पुत्र कादीर निवासी ग्राम सिकंदरपुर खास बस्ती थाना परशुरामपुर जिला बस्ती के द्वारा उपरोक्त युवक के मामा का पुत्र शादाब अहमद के जरिए सऊदी अरब बीजा टिकट हेतु युवक से ऑनलाइन नेवी ट्रांजैक्शन की सहायता से 143500 लेकर नकली वीजा दिए जाने और

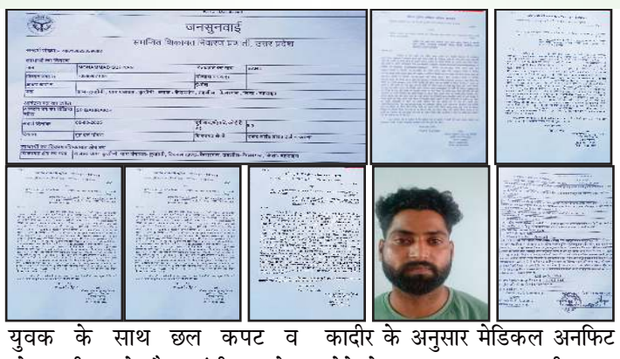

युवक के साथ छल कपट व धोखाधड़ी करने जैसा गंभीर आरोप लगाया है।उपरोक्त मामले के संबंध में पीड़ित मोहम्मद सुफियान ने जून माह में आईजीआरएस सं- 40018525017258 दर्ज करवाया था। उक्त आईजीआरएस से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक फिरोज अहमद पुत्र कादीर के अनुसार मेडिकल अनफिट होने के कारण युवाक सऊदी अरब नहीं जा पाया है। और युवक से लिए गए पैसे की वापसी 15 दिवस में कर दिया जाएगा। किंतु समय बीत जाने के बाद भी पैसा देने में युवक ने आज कल करके लंबा समय व्यक्तित्व किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण से यह प्रतीक होता है कि युवक के मन में कहीं ना कहीं बेईमानी व धोखा धड़ीं चरम पर है। उपरोक्त के क्रम में कैसरगंज थाने पर 2 अगस्त 25 को द्वितीय प्रार्थना पत्र देकर दण्डात्मक कार्यवाही करके पैसों के कुशल वापसी की मांग की है।उपरोक्त के संबंध में प्रभारी निरीक्षक परसरामपुर जनपद बस्ती ने बताया कि पीड़ित स्थानीय थाना कैसरगंज पर मुकदमा दर्ज कराएं कार्यवाही के क्रम जेल भेजा जाएगा।

उपरोक्त पीड़ित द्वारा 2 अगस्त 25 को दी गई तहरीर के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज सुरेन्द्र शर्मा के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क किया गया उनके फोन पर घंटी बजती रही विडम्बना रिसीव नहीं हो सका।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद

ई-निविदा सूचना संख्या: -EL/C/ADI/TRD/46/2025-26

25 केवी, एसी ओएचई और अन्य संबद्ध कार्यों का डिज़ाइन, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग

कार्य का नाम और स्थान: सोनासन से संबंधित 25 केवी, एसी ओएचई और अन्य संबद्ध कार्यों का डिज़ाइन, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग - लाइन संख्या 1 (एचएमटी छोर) के डीई का विस्तार करके 700x25 मीटर के आइलैंड पीएफ एप्रोच रोड और अन्य गुडशेड सुविधाओं के साथ दो लोडिंग लाइनें प्रदान करना।

कार्य की अनुमानित लागत: रु. 1,62,00,726/-

जमा की जाने वाली बयाना राशि: आईआरईपीएस पोर्टल पर निर्दिष्ट

बोली जमा करने और खोलने की तिथि एवं समय: आईआरईपीएस पोर्टल पर निर्दिष्ट

निविदा शुल्क: आईआरईपीएस पोर्टल पर निर्दिष्ट

कार्य की पूर्णता अवधि: 12 महीने

वेबसाइट विवरण और सूचना पट्ट जहाँ निविदा का विवरण देखा जा सकता है और कार्यालय का पता: सूचना पट्ट और उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण) का कार्यालय, पश्चिम रेलवे, निर्माण भवन- असरवा, अहमदाबाद (गुजरात-382345)

www.ireps.gov.in CPM046

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना संख्या S/51/2025, दिनांक 05.08.2025

क्र. नं.	वस्तु का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी.
426	रेलवे S & T प्रतिष्ठानों के लिए कम रखरखाव वाले लीड एसिड सेकेंडरी सेल, क्षमता 2V/80 AH	2342 नंग	26-अगस्त-25
427	रबर पैड	15989 नंग	02-सितंबर-25
428	प्राथमिक के लिए TPU रिंग का सेट	13616 सेट	02-सितंबर-25
429	होल्डिंग चुंबक वाल्व प्रकार EV 208 - 3VT	340 नंग	04-सितंबर-25
430	उच्च तन्यता वाले AAR H प्रकार के टाइट लॉक कपलर की आपूर्ति	20 नंग	04-सितंबर-25
431	ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व	12 नंग	08-सितंबर-25
432	वाहन इंटरफ़ेस यूनिट- 69241VI2AA 7101-VIU 2202-VIU	4 नंग	10-सितंबर-25
433	केंद्र धुरी शीर्ष	3925 नंग	06-अक्टूबर-25
434	BOXNHL वैगन के लिए Casnub 22HS बोगी	90 सेट	06-अक्टूबर-25

विस्तृत सूचना ईएमडी, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत निविदा शर्तों के संबंध में, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें और wr.indianrailways.gov.in

0470

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

राज्य में लखपति दीदी की संख्या 5 लाख के पार, गुजरात 10 लाख महिलाओं को बनाएगा आत्मनिर्भर

स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ीं हमारी माताएँ, बहनें तथा पुत्रियाँ विकसित भारत के निर्माण में एक मजबूत कड़ी हैं : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गांधीनगर, 7 अगस्त : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में 'लखपति दीदी' योजना शुरू की गई थी। 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना इस योजना का उद्देश्य है। गुजरात की महिलाओं को इस योजना का बड़े पैमाने पर लाभ मिले; इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप; जुलाई 2025 तक राज्य में करीब 5 लाख 96 महिलाओं की आय एक लाख रुपए से अधिक तक पहुँची है और वे गर्व के साथ गुजरात की 'लखपति दीदी' बनी हैं। आगामी समय में गुजरात 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनने में सहायक होकर महिला सशक्तिकरण का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्थापित करने को प्रतिबद्ध है।

राज्य में 10 लाख से अधिक संभावित लखपति दीदी की पहचान

राज्य के प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) द्वारा हाल में ऐसी 10.74 लाख महिलाओं की पहचान की गई है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं। पहचान की गईं संभावित लखपति दीदी की वर्तमान गतिविधियों तथा उनके पास

उपलब्ध स्रोतों, हुए खर्च एवं आय के विवरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल आजीविका रजिस्टर तैयार किया गया है। इस रिजस्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर पहचानी गईं लखपति दीदी को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, एसेट, आर्थिक सहायता एवं मार्केटिंग के लिए जरूरी सपोर्ट किया जा रहा है।

किस प्रकार काम करती है लखपति दीदी योजना ?

यह योजना स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ीं ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहायक बनती है, जिससे उनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो सके। महिलाएँ कृषि, पशुपालन, हस्तकला तथा अन्य स्थानीय क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा उन्हें प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं बाजार से जुड़ने की सुविधा दी जाती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। केन्द्र की गाइडलाइन के अनुसार लखपति दीदी के लिए निम्न विवरण के अनुसार आय गणना की जाती है :

* कृषि तथा उससे जुड़े व्यवसाय की वर्ष के दौरान कुल आय।
* नॉन-फार्म एक्टिविटी; जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज आदि की आय।
* परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, तो उसकी आय।
* फार्म तथा नॉन-फार्म व्यवसाय में मजदूरी कार्य से प्राप्त होने वाली आय।
* सरकार के योजनागत लाभों द्वारा प्राप्त हुई राशि।
* कमीशन, मानद् वेतन से प्राप्त आय।

124 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 10 हजार से अधिक सीआरपी को प्रशिक्षण

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गुजरात सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तहसील स्तर पर 124 मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (सीआरपी) को प्रशिक्षण दिया है। ये सीआरपी स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ीं महिलाओं को सहयोग देंगे। इस समग्र प्रक्रिया के लिए डिजिटल आजीविका रजिस्टर पर डेटा अपडेट किया जाता है, जो देखरेख के साथ महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग एवं मार्केट से कनेक्टिविटी देने में सहायक होता है।

सूरत की अंकिताबेन की आय एक वर्ष में 2 लाख रुपए हुई

लखपति दीदी कार्यक्रम को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक धरातल पर लागू किया है। इसके फलस्वरूप महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सूरत की महुवा तहसील के शेखपुर गाँव की अंकिताबेन पीनलभाई पटेल ने वर्ष 2024 में ड्रोन पायलट के रूप में कार्य शुरू किया था। केवल एक वर्ष में ही उन्होंने ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव कर 2 लाख रुपए की कमाई की है। यह कार्य शुरू करने से पहले वे परिवार के साथ खेती कार्य करके जीवन यापन करती थीं। अंकिताबेन कहती हैं, ह्यअब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। हमें ऑर्डर भी लगातार मिल रहे हैं और अच्छी आय भी हो रही है। मेरे हसबैंड की ओर से भी मुझे पर्याप्त सपोर्ट मिलता है। मेरे परिवार को मेरे इस कार्य से बहुत आर्थिक सहायता हुई है।ह्व

मुंबई पुलिस ने दुकानदार को किया गिरफ्तार, पान दुकान की आड़ में बेच रहा था ड्रग्स

(जीएनएस)।

मुंबई 6अगस्त : मुंबई पुलिस की विक्रोली यूनिट ने पान दुकान की आड़ में ड्रग्स बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1.84 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है. (न्यूज लेटेस्ट ली के अनुसार) पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनवर जमीरुल्ला अंसारी (48) के रूप में हुई है, जो मुंबई के विक्रोली इलाके स्थित टैगोर नगर में पान दुकान चलाता है. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपनी दुकान से मादक पदार्थ एमडी (मेथाम्फेटामाइन) बेच रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने ड्रग्स बेचते हुए आरोपी दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से कुल 92 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1.84 लाख रुपए बताई जा रही है. विक्रोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश

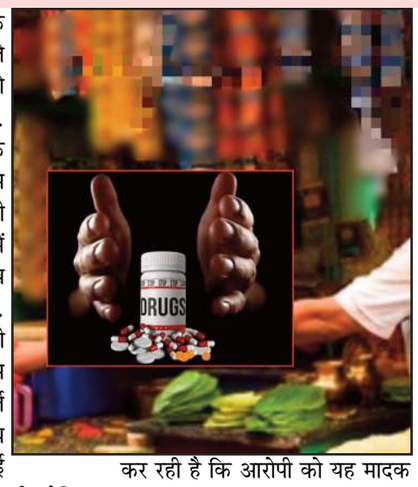

कर रही है कि आरोपी को यह मादक पदार्थ कहां से मिल रहा था और वह कितने समय से इस अवैध धंधे में लिप्त था. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि क्या उसका किसी बड़े गिरोह से संपर्क था या वह अकेले ही यह धंधा चला रहा था.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से अपनी पान दुकान की आड़ में यह गैरकानूनी काम कर रहा था, लेकिन अब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है. जांच में यह भी सामने आ सकता है कि वह किन-किन लोगों को यह ड्रग्स बेचता था. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल मच गई है. अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी.

गणेश उत्सव को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट, दिए गए सख्त सुरक्षा निर्देश

(जीएनएस)।

मुंबई में जल्द ही गणेशोत्सव की धूम मचने वाली है और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम पर बड़ी मीटिंग की. (एबीपी न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार) बुधवार को हुई इस मीटिंग में बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति और एक और बड़ी समिति के प्रतिनिधि मौजूद थे.खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, साथ में जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस आरती सिंह, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी, एडिशनल सीपी स्पेशल ब्रांच धनंजय कुलकर्णी और कई सीनियर अफसर भी पहुंचे.

महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान

पुलिस ने साफ-साफ कहा कि हर मंडल को उउळश कैमरे लगाने होंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखने होंगे और महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान

देना होगा. विसर्जन का रास्ता भी फिक्स रहेगा, उसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा. साथ ही, जुलूस के दौरान कोई हादसा न हो, इसके लिए पहले से सावधानी बरतने की अपील की गई है. पुलिस ने ये भी बताया कि इस बार विसर्जन के दिन समुद्र में पानी का लेवल करीब साढ़े चार मीटर तक बढ़ सकता है, इसलिए बीच किनारे ज्यादा सतर्कता रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

भीड़ वाले इलाकों में बनेंगे मेडिकल हेल्प सेंटर भीड़ और ट्रैफिक से निपटने के लिए मंडलों को सलाह दी गई है कि वॉलंटियर्स की मदद लें और भीड़ वाले इलाकों में मेडिकल हेल्प सेंटर भी बनाएं. दोनों समितियों ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस के साथ मिलकर सब नियमों का पालन करेंगे. पुलिस का कहना है कि इस बार गणेशोत्सव में माहौल सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस और गणेश मंडल एक टीम की तरह काम करेंगे.

बता दें, गणपति बप्पा की धूम अब धीरे-धीरे पूरे मुंबई में फैल रही है. हर रविवार को बड़े-बड़े मंडलों में गणपति आगमन के आयोजन हो रहे हैं. आगामी रविवार यानी 10, 15, 17 और 23 अगस्त को मुंबई के खेतवाड़ी, परेल, चेंबूर, दादर, सायन, धारावी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में गणेश मंडल अपने गणपति बप्पा का आगमन जुलूस निकालेंगे.

निजीकरण के विरोध में लगातार तीसरे दिन भी बनारस के समस्त बिजलिकर्मियो ने विरोध प्रदर्शन किया

दैनिक भीम वार्ता/संवाददाता जमील अख्तर

वाराणासी 7 अगस्त

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज तीसरे दिन भी बनारस के समस्त कार्यालयों पर बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जिसमें बनारस के अभियंता अवर अभियंता नियमित एवं संविदाकर्मी शामिल हुये।संघर्ष समिति के केंद्रीय आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय की तरह ही बनारस के तमाम बिजली कर्मचारी संविदा कर्मी जूनियर इंजीयिनर और अभियन्ता कल 08 अगस्त से 15 अगस्त तक सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर को बचाये रखने हेतु तिरंगा लेकर अभियान के तारतम्य में भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर दोपहर 2बजे से हाथ मे तिरंगा लेकर अग्रेंजो भारत छोड़ो आन्दोलन की तर्ज पर कारपोरेट सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो अभियान काकोरी क्रांति के 100 वर्ष पूरा होने पर चलाएंगे।विद्युत कर्मचारी संयुक्त

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसानों गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को बिजली के निजीकरण से होने वाली अपूरणीय क्षति से अवगत कराया जायेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली अकेली सेवा है जो अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को अलग अलग दाम पर मिलती है। इसका उद्देश्य यही है कि बिजली सबकी आवश्यकता है और गरीब उपभोक्ताओं को नुकसान उठाकर लागत से कम दाम पर बिजली आपूर्ति की जा सके। बिजली कारपोरेट घरानों के लिए व्यापार है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा है। इसीलिए बिजली के क्षेत्र में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी का प्राविधान है। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत प्रदेश के सबसे गरीब 42 जनपद आते हैं। इन 42 जनपदों की बिजली कारपोरेट घरानों के हवाले कर देना प्रदेश के विकास के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। निजीकरण के बाद बिजली की दरें कम से कम तीन गुनी हो जायेंगी। पॉवर कारपोरेशन ने निजी घरानों को सहूलियत देने के लिए बिजली की दरों में 45 प्रतिशत तक का इजाफा करने का प्रस्ताव इसीलिए विद्युत नियामक आयोग को भेज रखा है। इस प्रस्ताव से ही घरेलू बिजली की दरें 13 रुपए प्रति यूनिट तक हो जायेंगी।वक्ताओ ने बताया कि 08 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान में बिजली कर्मी आम जनता को निजीकरण के पीछे हो रही लूट से भी अवगत करायेंगे। लगभग एक लाख करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियों को मात्र 6500 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस पर बेचने का आरएफपी डॉक्यूमेंट पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने तैयार किया है। इसके अतिरिक्त 42 जनपदों की जमीन मात्र एक रुपए की लीज पर निजी घरानों को दी जायेगी जिसका संघर्ष समिति उ0प्र0 घोर विरोध एवं निंदा करती है।आज के कार्यक्रम को ई0 एस0के0सिंह ई0 नीरज बिंद अंकुर पाण्डेय संदीप कुमार पंकज यादव हेमंत श्रीवास्तव उदयभान दुबे विजय नारायण हिटलर अमित कुमार रोहित कुमार विजय सिंह नवीन कुमार ज्योतिप्रकाश जितेंद्र कुमार आदि ने सम्पन्न कराया।

कलीग को रेप के झूठे मामले में भेजा जेल, मांगी 1 करोड़ की फिरौती, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ी महिला बैंक कर्मी

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में उत्तरी मुंबई के चारकोप से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने प्राइवेट बैंक की एक महिला कर्मचारी को ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया है.महिला पर अपने पूर्व कलीग को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाकर 1 करोड़ का एक्सटॉर्शन मांगने का आरोप है. पुलिस ने आरबीएल बैंक की कर्मचारी डॉली कोटक को गिरफ्तार कर लिया है. (आज तक के रिपोर्ट के अनुसार) डॉली पर अपने आईटी प्रोफेशनल कलीग को गलत तरीके से जेल भेजने, कथित तौर पर एक झूठे बलात्कार के मामले की साजिश रचने और उससे ₹1 करोड़ की जबरन वसूली करने का प्रयास करने का आरोप है.

आरोप है कि महिला पीड़ित को जेल भेजने से शांत नहीं हुई, डॉली कोटक ने कथित तौर पर अदालत

परिसर में पीड़ित की बहन से जमानत के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफि केट बयान के बदले ₹1 करोड़ की मांग भी की. इसके साथ ही धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा. बार-बार मना करने के बावजूद, उसने लगातार फोन कॉल के माध्यम से पीड़ित पर दबाव बनाना जारी रखा. अंततः उसने अपने वकील के कार्यालय में एक मीटिंग की जहां उसने 1 करोड़ की जबरन वसूली की मांग दोहराई. इतना ही नहीं डॉली कोटक पर आरोप है कि उन्होंने बैंक कर्मचारियों की मदद से आईटी पेशेवर और उनकी पत्नी के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा तक अवैध रूप से पहुंच भी बनाई है. डॉली ने पीड़ित के अकाउंट और गूगल से जुड़े मोबाइल नंबर हटाकर अपना मोबाइल नंबर ऐड किया जिसके कारण ऑनलाइन बैंकिंग विवरण, जीपीएस लोकेशन हिस्ट्री, निजी तस्वीरें और लोकेशन की जानकारी डॉली को मिलने लगी. मई 2024 में, पीड़ित को कोटक के नंबर से एक धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें लिखा था 'तुम कभी नहीं जीतोगे और दर्द में मरोगे. पैसे दो या जेल में मरो...'. यह उत्पीड़न उनके पेशेवर जीवन तक भी फैल गया जब डॉली कोटक ने कथित तौर पर उनके एम्प्लॉयर के एचआर सेक्शन को ईमेल किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी नौकरी समाप्त हो गई और उन्हें भारी दबाव में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा.बार-बार उत्पीड़न और पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने के बाद, पीड़ित ने बोरीवली मजिस्ट्रेट से राहत की गुहार लगाई, जिन्होंने चारकोप पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. इस मामले में पुलिस ने डॉली अरविंद कोटक, प्रमिला वास एचडीएफसी बैंक के संबंधित कर्मचारी और सागर अरविंद कोटक पर मामला दर्ज किया है.

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 प्रवर्तित किया गया

लखनऊ : 07 अगस्त, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा अन्य निर्णयों के साथ निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने निजी क्षेत्र के अन्तर्गत वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना हेतु उसकी प्रायोजक संस्था को खतौनियों में 'लाला फतेह चन्द चैरिटेबल ट्रस्ट' के स्थान पर 'फतेह चन्द चैरिटेबल ट्रस्ट' अंकित कराकर उसकी प्रतियां अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत किये जाने की शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 की धारा-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत आशय-पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 प्रवर्तित किया गया है। इस अधिनियम की धारा-4 में नये विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने, धारा-5 में प्रस्ताव का मूल्यांकन किये जाने व धारा-6 में आशय-पत्र निर्गत किये जाने विषयक प्राविधान विहित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की प्रक्रिया को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियमावली, 2021 का प्रख्यापन किया गया है। इस नियमावली के नियम-14 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष मन्तव्य एवं संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है।

उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 में वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना हेतु उसकी प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी। इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना ग्राम हुसैनपुर बोपाडा, तहसील खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में 23.3349 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित की गयी है। उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के क्रम में वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना हेतु उसकी प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र निर्गत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

वर्तमान ग्राम प्रधान की लापरवाही से नहीं हुआ गांव का विकास ग्राम प्रधान बेहाल जनता परेशान खड़ंजा मार्ग बारिश की वजह से दलदलों में तब्दील तथा बच्चों व ग्रामीणों का लगा रहता है आना जाना

वर्तमान ग्राम प्रधान की लापरवाही से नहीं हुआ गांव का विकास ग्राम प्रधान बेहाल जनता परेशान खड़ंजा मार्ग बारिश की वजह से दलदलों में तब्दील तथा बच्चों व ग्रामीणों का लगा रहता है आना जाना

(जीएनएस)।

फतेहपुर थाना थरियांव क्षेत्र के हसवा ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बक्सपुर में खड़ंजा मार्ग बारिश की वजह से जल भराव बना रहता है तथा कहीं गड्ढे कहीं कीचड़ इस प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं जिसमें की समस्त ग्रामीण व बच्चों का आना जाना लगा रहता है तथा

इसी के पश्चात बताते चले कि प्रतिदिन स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है फिर भी ग्राम प्रधान व उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी निगेहबानी नही की जाती इसलिए गांव के लोग दिक्कतों का सामना करते है तथा लोगो का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान को सूचित किया कि इस खडंजा मार्ग का निर्माण इंटरलॉकिंग या ईट के खड़ंजे का सही तरीके से मरम्मती करण या निर्माण करा दीजिए लेकिन ग्राम प्रधान ग्रामीणों की बातों का कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान वा उच्च अधिकारियों से नाराजगी जताई। तथा ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हमारे ही गांव में आज तक किसी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ तो बताइए इस प्रकार हमारा गांव किस श्रेणी में होगा इन सभी मुद्दों पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी क्या कहना चाहेंगे।